राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 352/2002

पदम चंद

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य

----प्रतिवादी

संबंधित के साथ

एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 2734/2003

पदम चंद

----याचिकाकर्ता

बनाम

भारतीय जीवन बीमा निगम और अन्य

----प्रतिवादी

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री अछराज सिंह सलूजा

प्रतिवादी की ओर से : श्री राजीव पुरोहित

माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण मोंगा

आदेश (मौखिक)

13/02/2025

1. चूंकि उपरोक्त शीर्षक वाली दोनों याचिकाओं में कानून और तथ्य के समान प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन्हें इस सामान्य आदेश के माध्यम से तय किया जा रहा है।

याचिकाकर्ता दिनांक 12.06.1999 (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 352/2002 में अनुलग्नक 10) और दिनांक 21.03.2000 (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2734/2003 में अनुलग्नक 12) के दंड आदेशों को चुनौती देता है। वह दिनांक

15.12.1999 (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 352/2002 में अनुलग्नक 12) और दिनांक 31.08.2000 (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2734/2003 में अनुलग्नक 14) के उन आदेशों को भी रद्द करने की मांग करता है, जिनके माध्यम से दंड आदेशों के विरुद्ध अपीलों को खारिज कर दिया गया था। इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता दिनांक 24.11.2000 (एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 352/2002 में अनुलग्नक 14) के आदेश को रद्द करने की मांग करता है, जिसने दिनांक 12.06.1999 और 15.12.1999 के आदेशों के विरुद्ध उसकी याचिका को खारिज कर दिया था।

2. याचिका संख्या 352/2002 में बताए गए प्रासंगिक तथ्य, अनावश्यक विवरणों को हटाकर, इस प्रकार हैं: याचिकाकर्ता को शुरू में 18.09.1987 को चपरासी के रूप में नियुक्त किया गया था और बाद में 13.08.1997 को सहायक के पद पर पदोन्नत किया गया था। याचिकाकर्ता को दिनांक 23.06.1998 (अनुलग्नक 1) का एक आरोप पत्र दिया गया था, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि उसके विरुद्ध जुआ खेलने के लिए प्राथमिकी दर्ज की गई थी और उसने अपने वरिष्ठों और सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार किया था। जवाब में, याचिकाकर्ता ने 15.07.1998 (अनुलग्नक 2) को अपना जवाब प्रस्तुत किया।

2.1. एक जाँच आयोजित करने पर, जाँच अधिकारी ने एक रिपोर्ट (अनुलग्नक 7) प्रस्तुत की, जिसमें याचिकाकर्ता के विरुद्ध आरोपों को सिद्ध पाया गया। परिणामस्वरूप, दिनांक 01.05.1999 (अनुलग्नक 8) का एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, जिस पर याचिकाकर्ता ने अपना जवाब (अनुलग्नक 9) प्रस्तुत किया। सभी उपलब्ध सामग्री पर विचार करते हुए, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने दिनांक 12.06.1999 (अनुलग्नक 10) का एक आदेश जारी किया, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल वेतन को एक चरण तक कम करने का दंड लगाया गया।

2.3. रिट याचिका संख्या 2734/2003 में, याचिकाकर्ता के विरुद्ध दिनांक 12.03.1999 (अनुलग्नक 3) का एक और आरोप पत्र जारी किया गया था, जिसमें एक अन्य कर्मचारी पर शारीरिक हमला करने और दुराचार की और घटनाओं का आरोप लगाया गया था। उचित जाँच के बाद, दिनांक 21.03.2000 को एक दंड आदेश पारित किया गया, जिसमें याचिकाकर्ता के मूल वेतन को समय-मान में एक चरण तक कम कर दिया गया। इस आदेश के विरुद्ध याचिकाकर्ता की अपील को दिनांक 31.08.2000 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया।

2.4. इसलिए, ये याचिकाएँ दायर की गई हैं।

3. प्रतिवादियों ने, अन्य बातों के साथ-साथ, जोर देकर कहा कि याचिकाकर्ता को पुलिस ने जुआ खेलते हुए रंगे हाथों पकड़ा था और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद उसे हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद, कानून की उचित प्रक्रिया का पालन करने के बाद आरोप पत्र जारी किया गया। जाँच अधिकारी ने संपूर्ण रिकॉर्ड, याचिकाकर्ता के रुख और प्रस्तुत साक्ष्य पर विचार करने के बाद याचिकाकर्ता को आरोपों का दोषी पाया। अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने, याचिकाकर्ता के जवाब सहित सभी सामग्री की समीक्षा करने के बाद, चुनौतीपूर्ण दंड लगाए। अपीलीय प्राधिकारी ने दंड को बरकरार रखा, इसे दुराचार के अनुरूप और उचित माना। इस प्रकार, वे तर्क देते हैं कि चुनौती वाले आदेश कानून के अनुसार पारित किए गए थे और इस न्यायालय द्वारा किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. उपरोक्त के आलोक में, मैंने प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है और मामले की फ़ाइलों का अवलोकन किया है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने मोटे तौर पर रिट याचिका में उठाए गए आधारों पर जोर दिया है। वह तर्क देते हैं कि जिस मामले में याचिकाकर्ता को गिरफ्तार किया गया था, वह प्रासंगिक आचरण नियमों के तहत दुराचार का गठन नहीं करता है, क्योंकि कथित अपराध कार्यालय समय के बाहर और कार्यालय परिसर के बाहर हुआ था।

5.1. इसके अलावा, याचिकाकर्ता जोर देता है कि उसे अपना बचाव करने का उचित अवसर नहीं दिया गया, जिससे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ। वह तर्क देता है कि जाँच अधिकारी ने इस तरह कार्यवाही की जैसे कि याचिकाकर्ता द्वारा दोष स्वीकार करने के कथित आधार पर आरोप पहले ही सिद्ध हो चुके थे, भले ही विभाग की ओर से किसी भी गवाह की जाँच नहीं की गई थी।

5.2. इसके अतिरिक्त, अनुशासनात्मक प्राधिकारी ने, याचिकाकर्ता के जवाब को खारिज करने का कोई तर्क दिए बिना, दंड लगाए। दूसरे आरोप पत्र के संबंध में, याचिकाकर्ता का दावा है कि उसे प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट प्रदान नहीं की गई थी और उसे बचाव सहायक को बदलने की अनुमति से वंचित कर दिया गया था, जिससे उसे अपना बचाव स्वयं करने के लिए मजबूर होना पड़ा। वह तर्क देता है कि जाँच अधिकारी ने केवल यह दर्ज किया कि विभिन्न गवाहों की गवाही ने उसके विरुद्ध आरोपों को सिद्ध किया।

5.3. याचिकाकर्ता आगे तर्क देता है कि अपीलीय प्राधिकारी उसके किसी भी अभ्यावेदन पर विचार करने में विफल रहा और न तो किसी भी मामले में तर्कपूर्ण आदेश पारित किया।

5.4. इसके विरोध में, प्रतिवादियों के विद्वान अधिवक्ता ने अपने जवाब में उल्लिखित बचाव को दोहराया।

6. मैं अब इस आदेश के अगले भाग में प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए आगे बढ़ूँगा।

7. सबसे पहले, दोनों याचिकाओं में जाँच रिपोर्टों का संदर्भ लिया जाए, जिनके अनुवादित संस्करण (जैसा कि उच्च न्यायालय के आधिकारिक अनुवादक द्वारा प्रदान किए गए हैं) नीचे दिए गए हैं:

एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 352/2002 में जाँच रिपोर्ट

"भारतीय जीवन बीमा निगम (कर्मचारी) विनियम *1960* के विनियम *39* के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई।

पी.सी. सोगरा, सहायक, वेतन संख्या *146901*, शाखा कार्यालय, प्रतापगढ़ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।

:- जाँच रिपोर्ट :-

वरिष्ठ मंडल प्रबंधक के दिनांक *6* अगस्त, *98* के आदेश द्वारा, मुझे उक्त जाँच कार्यवाही में जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था और श्री भगवान सिंह प्रशासनिक अधिकारी, मंडल कार्यालय, उदयपुर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया था।

श्री पी.सी. सोगरा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पहली तारीख *26.08.98* तय की गई थी, जिसमें आरोप पत्र में उल्लिखित सभी दस्तावेज प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा दोषी कर्मचारी को दिए गए थे और उसे आरोप पत्र पढ़कर सुनाया गया था, इसके साथ ही जाँच अधिकारी ने दोषी कर्मचारी से बचाव सहायक और अन्य दस्तावेजों की आवश्यकताओं के बारे में पूछा, जिसके बाद अगली सुनवाई की तारीख *25.09.98* तय की गई थी, जिसके तहत दोषी कर्मचारी से बचाव सहायक की आवश्यकता के संबंध में जानकारी मांगी गई थी, लेकिन चूंकि दोषी कर्मचारी ने बाद में जानकारी दी, इसलिए सुनवाई की तारीखें *06.11.98* और *19.11.98* तय की गईं, फिर भी चूंकि उसने जानकारी नहीं दी, इसलिए अंतिम मौका दिया गया और सुनवाई की तारीख *28.11.98* तय की गई। *28.11.98*, *07.12.98* और *21.12.98* को आयोजित सुनवाई के दौरान, विभिन्न मुद्दों पर तर्क दिए गए। इसके बाद *04.02.99* को प्रतापगढ़ शाखा मुख्यालय में अंतिम सुनवाई हुई, जहाँ दोषी कर्मचारी तैनात है।

आरोप पत्र में उल्लिखित निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी पहली सुनवाई के दौरान दोषी कर्मचारी को दी गई थी*: -*

1. पी.*--1* प्रतापगढ़ शाखा कार्यालय के कर्मचारियों का दिनांक *13.09.97* का पत्र
2. पी.*--2* प्रशासनिक अधिकारी, प्रतापगढ़ का दिनांक *13.09.97* का कार्यालय नोट
3. पी.*--3* शाखा प्रबंधन को लिखे गए शाखा कार्यालय के विभिन्न कर्मचारियों का पत्र।
4. पी.*--4* श्री डी.एल. परमार, यू.डी.ए. प्रतापगढ़ का शाखा प्रबंधक को दिया गया दिनांक *13.09.97* का कार्यालय नोट।
5. पी.*--5* प्राथमिकी संख्या *144/97* दिनांक *– 18.04.97*।

इसके अलावा, दोषी कर्मचारी द्वारा मांगे गए निम्नलिखित दस्तावेजों की फोटोकॉपी दी गई*: -*

1. डी.*--1* सितंबर, *97* माह के उपस्थिति रजिस्टर की प्रति।
2. डी.*--2* श्री संतोष गुप्ता के आकस्मिक अवकाश रजिस्टर की प्रति।
3. डी.*--3* श्री संतोष गुप्ता का दिनांक *18.09.97* का आकस्मिक अवकाश आवेदन की प्रति।

बहस के दौरान दोषी कर्मचारी द्वारा आरोप पत्र में उल्लिखित आरोपों से संबंधित विवरण*:-*

1. आरोप संख्या *- 1,* दोषी कर्मचारी द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार किया गया।
2. आरोप संख्या *-2,* दोषी कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया गया।
3. आरोप संख्या *-3,* दोषी कर्मचारी ने स्वीकार किया और कहा कि उसने जानकारी देना उचित नहीं समझा क्योंकि वह *40* घंटे से कम समय के लिए हिरासत में था।
4. आरोप संख्या *-4,* दोषी कर्मचारी द्वारा स्वीकार किया गया।
5. आरोप संख्या *- 5,* दोषी कर्मचारी ने इस संबंध में कुछ नहीं कहा। अतः यह स्व-स्पष्ट है कि इसे स्वीकार कर लिया गया था।

अपनी लंबी बहसों के दौरान, दोषी कर्मचारी ने आरोपों के जवाब में कोई विशिष्ट तर्क नहीं उठाया। उसने केवल शाखा में चल रही अनियमितताओं के संबंध में तर्क देना जारी रखा और अपने तर्कों को केवल ऐसी अनियमितताओं पर आधारित किया, जबकि उसे बार-बार उस पर लगाए गए आरोपों के संबंध में अपना तर्क उठाने के लिए कहा गया था। लेकिन उसने केवल यह तर्क दिया कि सभी आरोप इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि उसने शाखा में चल रही उक्त अनियमितताओं को उजागर करने की कोशिश की थी। दोषी कर्मचारी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी और जाँच अधिकारी द्वारा बार-बार आरोपों के संबंध में तर्क देने के लिए कहा गया था, लेकिन तब भी उसने कोई प्रमाण या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया। उसने केवल यह कहा कि जिन व्यक्तियों का उसने तर्कों में उल्लेख किया था, उन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से साक्ष्य में प्रस्तुत किया जाना चाहिए, लेकिन प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया।

श्री पी.सी. सोगरा ने अपनी समीक्षा में केवल तर्कों को दोहराया है और आरोपों के बचाव के समर्थन में कुछ नहीं कहा है।

इसलिए, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि भारतीय जीवन बीमा निगम *(*कर्मचारी*)* विनियम, *1960* की धारा *21*, *24* और *30*, धारा *30 (39)* दोषी कर्मचारी पर लागू होती है। इसलिए, विनियम, *1960* की धारा *39* की उप-धारा *1* के तहत खंड ए से जी के अनुसार दोषी कर्मचारी के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है।"

हस्ताक्षरित/-
*(*डी.एल. काबरा*)*
प्रबंधक

संलग्नक*:* उपरोक्त अनुसार।

एस.बी.सी.डब्ल्यू.पी. संख्या 2734/2003 में जाँच रिपोर्ट

भारतीय जीवन बीमा निगम
मंडल कार्यालय:- उदयपुर

भारतीय जीवन बीमा निगम *(*कर्मचारी*)* विनियम *1960*, विनियम *39* के तहत श्री पी.सी. सोगरा, सहायक, वेतन संख्या - *146901*, प्रतापगढ़ शाखा के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई।

जाँच रिपोर्ट

श्री पदमचंद सोगरा को सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिनांक *12.03.99* का एक आरोप पत्र जारी किया गया था। आरोप पत्र में निम्नलिखित आरोप शामिल थे*:-*

कि श्री पदमचंद सोगरा ने *13.02.99* को सुबह लगभग *10.00* बजे कार्यालय परिसर में श्री राकेश राजोरा, सहायक, पर हमला किया और गाली-गलौज की।

कि श्री पदमचंद सोगरा ने घटना के समय उपस्थित शाखा कार्यालय, प्रतापगढ़ में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों को धमकाया और कार्यालय में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया।

श्री पदमचंद सोगरा द्वारा उपरोक्त आरोप पत्र का जवाब *29.04.99* को मंडल कार्यालय, उदयपुर में प्राप्त हुआ था। *(*प्रदर्श डी-*1)*

दिनांक *02.06.99* के आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकारी ने मुझे उपरोक्त मामले में जाँच अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

दिनांक *02.06.99* के एक आदेश द्वारा, सक्षम प्राधिकारी ने श्री भगवान चेल्लारामानी, प्रशासनिक अधिकारी *(*कानून और आवास*)* को जाँच के दौरान प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करने के लिए प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया।

18.06.99 को, दोषी कर्मचारी, श्री पदमचंद सोगरा को *28.06.99* को सुबह *10.30* बजे मंडल कार्यालय में मेरे कक्ष में सुनवाई में उपस्थित होने और यदि उसे अपना बचाव करने के लिए एक सहकर्मी की सहायता की आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के लिए मेरे हस्ताक्षर के तहत एक नोटिस जारी किया गया था। इसकी एक प्रति प्रस्तुतकर्ता अधिकारी, श्री भगवान चेल्लारामानी को भेजी गई थी।

पहली सुनवाई *28.06.99* को निर्धारित समय पर मेरे कक्ष में शुरू हुई। इस दिन, दोषी कर्मचारी श्री पदमचंद सोगरा, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी श्री भगवान चेलारमानी, श्री सुरेश चंद मीणा, आशुलिपिक और मैं उपस्थित थे। सुनवाई के दौरान, आरोप पत्र में उल्लिखित दोनों आरोप श्री पदमचंद सोगरा को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा पढ़कर सुनाए गए और आरोप पत्र में उल्लिखित *24* दस्तावेजों की प्रतियां प्रदान की गईं। *(*प्रदर्शपी-*1* से पी-*24)*

दोषी कर्मचारी श्री पदमचंद सोगरा से पूछा गया कि वह अपने बचाव सहायक का सहमति पत्र और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी नियुक्ति पत्र कब जमा करेंगे। इसके जवाब में, दोषी कर्मचारी ने कहा कि वह *15* दिनों के भीतर अपने बचाव सहायक का नियुक्ति पत्र जमा कर देगा।

दोषी कर्मचारी से उसके गवाहों और दस्तावेजों की सूची भी जमा करने के लिए कहा गया था। जवाब में, दोषी कर्मचारी ने कहा कि वह अगली सुनवाई में वही जमा करेगा।

फिर मैंने दोषी कर्मचारी से आरोप संख्या *01* और *02* के संबंध में पूछा कि क्या वह उन्हें स्वीकार करता है, उसने आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट और स्थापना मैनुअल खंड परिशिष्ट-*02* प्रदान करने के लिए कहा। जब मैंने पूछा कि स्थापना मैनुअल खंड परिशिष्ट-*02* क्या दस्तावेज है, जो जाँच कार्यवाही से संबंधित है, तो दोषी कर्मचारी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे सका।

सुनवाई *28.06.99* को पूरी हुई और अगली सुनवाई *17.07.99* के लिए निर्धारित की गई। चूंकि सभी गवाह शाखा कार्यालय, प्रतापगढ़ में कार्यरत हैं, इसलिए सक्षम अधिकारी ने *17.07.99* को सुनवाई प्रतापगढ़ शाखा में ही आयोजित करने का आदेश दिया। इसकी सूचना दोषी कर्मचारी को मेरे दिनांक *06.07.99* के पत्र के माध्यम से दी गई थी। एक अन्य पत्र दिनांक *10.07.99* द्वारा, दोषी कर्मचारी के बचाव सहायक, श्री महेश सांचोरा, यू.डी.ए., शाखा, सी.ए.बी., उदयपुर को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उनकी नियुक्ति के बारे में सूचित किया गया था और उन्हें *17.07.99* को सुनवाई के दौरान शाखा कार्यालय प्रतापगढ़ में उपस्थित रहने के लिए कहा गया था।

अगली सुनवाई *17.07.99* को प्रतापगढ़ शाखा में निर्धारित की गई थी, लेकिन दोषी कर्मचारी कार्यवाही में उपस्थित नहीं हुआ और उससे कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई। अगली सुनवाई *29.07.99* को सुबह *10.00* बजे शाखा कार्यालय, प्रतापगढ़ में निर्धारित की गई थी, जिसकी सूचना दोषी कर्मचारी को दिनांक *17.07.99* के पत्र द्वारा दी गई थी।

कार्यवाही *29.07.99* को सुबह *11.00* बजे शुरू हुई। कार्यवाही में, दोषी कर्मचारी श्री सोगरा के बचाव सहायक, श्री महेश सांचोरा भी उपस्थित थे, लेकिन जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई, दोषी कर्मचारी ने मुझे अपने बचाव सहायक को बदलने के लिए एक पत्र दिया, श्री एम.ए. काने, जो अजमेर मंडल में कार्यरत हैं। दोषी कर्मचारी श्री सोगरा ने अपने बचाव सहायक श्री सांचोरा को भी सूचित नहीं किया कि वह उनकी सेवाएं नहीं लेना चाहता। जबकि बचाव

सहायक को दोषी कर्मचारी के अनुरोध पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया था।

19.07.99 को उपस्थित न रहना और *29.07.99* को सुनवाई शुरू होते ही बचाव सहायक को बदलने के लिए एक आवेदन देना, जो अजमेर मंडल कार्यालय में कार्यरत है, जानबूझकर कार्यवाही में देरी करने के लिए किया गया था। जबकि उसका बचाव सहायक, जिसे दोषी कर्मचारी के अनुरोध पर नियुक्त किया गया था, अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए उपलब्ध था। *29.07.99* की कार्यवाही आयोजित नहीं की जा सकी क्योंकि दोषी कर्मचारी ने बचाव सहायक को बदलने पर जोर दिया, जिसके लिए उसने उसी दिन एक आवेदन प्रस्तुत किया था। *29.07.99* की कार्यवाही शाम *5.00* बजे समाप्त हुई और अगली सुनवाई *16.09.99* को प्रतापगढ़ शाखा में निर्धारित की गई।

बचाव सहायक को बदलने के लिए दोषी कर्मचारी के आवेदन पर, सक्षम प्राधिकारी ने अपने दिनांक *02.08.99* के पत्र द्वारा सूचित किया कि चूंकि श्री महेश सांचोरा को दोषी कर्मचारी की इच्छा के अनुसार बचाव सहायक के रूप में नियुक्त किया गया था और उनकी उपलब्धता भी है, इसलिए इस समय बचाव सहायक को बदलने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, और इसलिए, दोषी कर्मचारी से कार्यवाही में अपना सहयोग बढ़ाकर कार्यवाही के शीघ्र निपटान में सहयोग करने की उम्मीद की गई थी।

16.09.99 को सुबह *11.45* बजे प्रतापगढ़ शाखा कार्यालय में कार्यवाही फिर से शुरू हुई। कार्यवाही शुरू होते ही, दोषी कर्मचारी ने फिर से अपने बचाव सहायक को बदलने पर जोर दिया, जबकि सक्षम अधिकारी ने अपने दिनांक *02.08.99* के पत्र द्वारा दोषी कर्मचारी के अनुरोध को अस्वीकार कर दिया था।

दोषी कर्मचारी ने फिर से स्थापना मैनुअल परिशिष्ट-*02* प्रदान करने की मांग की। चूंकि दोषी कर्मचारी यह स्पष्ट रूप से बताने की स्थिति में नहीं था कि स्थापना मैनुअल परिशिष्ट-*02* कौन सा दस्तावेज है और इसका कार्यवाही से क्या संबंध है, इसलिए यह तथाकथित स्थापना मैनुअल उसे प्रदान नहीं किया जा सका। दोषी कर्मचारी को स्वयं इस स्थापना मैनुअल के बारे में पता नहीं था। वह केवल ऐसी मांग करना चाहता था जिससे कार्यवाही में अनावश्यक देरी हो।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी ने गवाहों को पेश करने के लिए कहा, जिसे जाँच अधिकारी ने अनुमति दी। कार्यवाही में निम्नलिखित गवाहों को पेश किया गया:-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**
1	श्री अवकाश सिंघवी	सहायक
2	श्री नरेंद्र कुमार सोनी	सहायक
3	श्री राजेश कसोदनिया	सहायक
4	श्री जगदीश चंद	उप-कर्मचारी
5	श्री राकेश राजेरा	सहायक
6	श्री राजेंद्र लाहोटी	सहायक
7	श्री अरविंद जैन	सहायक
8	श्री ओमप्रकाश गुर्जर	सहायक

9	श्री डूंगर सिंह रावत	उप-कर्मचारी
10	श्री उमेश चंद साल्वी	उप-कर्मचारी
11	श्री अमित सोमानी	सहायक
12	श्रीमती आभा लाहोटी	कैशियर
13	श्री गोविंद सिंह चुंडावत	सहायक
14	श्री भरत लाल	सहायक

सभी गवाहों के बयान एक-एक करके दर्ज किए गए और दोषी कर्मचारी को प्रत्येक गवाह से जिरह करने का अवसर दिया गया। लेकिन दोषी कर्मचारी ने बार-बार कहा कि जब उसे अपनी पसंद का बचाव सहायक मिलेगा तभी वह सभी गवाहों को फिर से बुलाएगा, जो मांग उचित नहीं थी और यह केवल कार्यवाही में देरी करने के लिए की गई थी।

सभी गवाहों ने अपने बयानों में पुष्टि की कि दोषी कर्मचारी श्री सोगरा ने सहायक श्री राकेश राजोरा को पीटा था। गवाहों के बयानों से यह तथ्य भी सामने आया कि श्री सोगरा अक्सर कार्यालय में गाली-गलौज और धमकी दिया करते थे।

कार्यवाही *16.09.99* को समाप्त कर दी गई।

हालाँकि कार्यवाही *16.09.99* को समाप्त कर दी गई थी, फिर भी सक्षम अधिकारी ने अपने दिनांक *20.09.99* के पत्र द्वारा मुझे एक बार फिर से कार्यवाही शुरू करने के लिए कहा ताकि श्री सोगरा अपना बचाव प्रस्तुत कर सकें।

सक्षम अधिकारी के निर्देशों के अनुसार, कार्यवाही *06.10.99* को मंडल कार्यालय में मेरे कक्ष में फिर से आयोजित की गई, जिसकी सूचना दोषी कर्मचारी को दिनांक *28.09.99* के पत्र द्वारा भेजी गई थी।

सुनवाई *06.10.99* को सुबह *11.35* बजे मेरे कक्ष में शुरू हुई। सुनवाई की शुरुआत में ही दोषी कर्मचारी को बताया गया कि हालाँकि कार्यवाही *16.09.99* को समाप्त हो गई थी, लेकिन सक्षम अधिकारी ने उसे एक बार फिर से अपना बचाव/गवाह आदि मांगने के लिए कहा है, इसलिए, आप अपना बचाव/गवाह प्रस्तुत कर सकते हैं।

इस पर, दोषी कर्मचारी ने फिर से वही बात दोहराई कि उसने मुझसे कानून मांगा था, जिसमें उन सभी बातों का उल्लेख है कि जाँच कार्यवाही कैसे की जानी चाहिए, जाँच अधिकारी कैसे जाँच करेगा, दोषी कर्मचारी के अधिकार क्या होंगे, प्रस्तुतकर्ता अधिकारी के कर्तव्य/अधिकार क्या हैं, इन सभी कानूनी बातों को जाने बिना, वह अपना बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता। दोषी कर्मचारी ने यह भी कहा कि बचाव सहायक एक विभागीय सेवा कर्मचारी है और जब भी उसे आवश्यकता होगी, वह कार्यवाही के दौरान बचाव सहायक को बदलने के लिए आवेदन कर सकता है। जबकि दोषी कर्मचारी के आवेदन पर, सक्षम अधिकारी ने श्री महेश सांचोरा यू.डी.ए., शाखा सी.ए.बी., उदयपुर को उसका बचाव सहायक होने की अनुमति दी थी, जिसकी सूचना सक्षम अधिकारी ने दिनांक *09.07.99* के पत्र द्वारा दोषी कर्मचारी को दी थी।

बार-बार अनुरोध के बावजूद, दोषी कर्मचारी अपने बचाव में कोई गवाह/दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका और यह कहना शुरू कर दिया कि जब तक उसे स्थापना - *2* मैनुअल उपलब्ध नहीं कराया जाता, तब तक वह अपना बचाव प्रस्तुत नहीं कर सकता। ये सभी बातें कार्यवाही को अनावश्यक रूप से लंबा खींचने के दोषी कर्मचारी के इरादे को प्रकट करती हैं। सुनवाई *06.10.99* को पूरी हुई।

प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। यह लिखित बयान *18.10.99* को प्रस्तुत किया गया था। प्रदर्शसंख्या पी-*27*

20.10.99 को, उपरोक्त लिखित बयान की प्रमाणित प्रति दोषी कर्मचारी श्री सोगरा को भेजी गई थी और उसे इसकी प्राप्ति के *15* दिनों के भीतर अपना लिखित बयान प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। दोषी कर्मचारी ने अपने दिनांक *02.11.99* के पत्र में, जो *08.11.99* को प्राप्त हुआ था, जवाब प्रस्तुत करने में देरी के लिए माफी मांगी और *15* दिन का और समय मांगा, जिसे दिनांक *17.11.99* के पत्र द्वारा अनुमति दी गई थी। अंत में दोषी कर्मचारी ने अपना लिखित बयान दिनांक *27.11.99 (*एक महीने और सात दिन बाद जो मुझे *04.12.99* को प्राप्त हुआ*)* दिया। प्रदर्शसंख्या डी-*3*।

उपरोक्त मामले में, मैंने आरोप पत्र में लगाए गए आरोपों, दोषी कर्मचारी के जवाब प्रदर्श संख्या डी-*1* और डी-*3*, प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श संख्या पी-*1* से पी-*27* और उपरोक्त उल्लिखित गवाहों द्वारा दी गई गवाही का अध्ययन किया है। इस आधार पर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि*:-*

<u>आरोप संख्या - *01:-*</u>

श्री पदमचंद सोगरा ने शाखा कार्यालय में श्री राकेश राजोरा, सहायक, पर हमला किया और गाली-गलौज की।

इस संबंध में गवाहों, श्री अवकाश सिंघवी, नरेंद्र कुमार सोनी ने अपनी गवाही में स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने श्री सोगरा को राकेश राजोरा पर हमला करते देखा। इसके अलावा, प्रदर्शसंख्या *1* से *24* के माध्यम से, प्रत्येक कर्मचारी ने अपनी गवाही में पुष्टि की है कि *13.02.99* को सुबह लगभग *10.00* बजे, श्री राकेश राजोरा को अन्य कार्यालय कर्मचारियों द्वारा श्री पदमचंद सोगरा से बचाया जा रहा था, जो उसे पीटने के बाद गाली दे रहा था।

निस्संदेह, आरोप संख्या *1* श्री पदमचंद सोगरा के विरुद्ध सिद्ध होता है।

<u>आरोप संख्या - *02:-*</u>

यह आरोप प्रदर्श संख्या *1* से *24* में लिखित बयानों और गवाहों श्री राजेश कसोदनिया, जगदीश चंद्र, राजेंद्र लाहोटी, अरविंद जैन, ओमप्रकाश गुर्जर, उमेशचंद साल्वी और अमित सोमानी की गवाही से स्पष्ट और पुष्टि होता है कि श्री सोगरा ने *13.02.99* को सुबह लगभग *10.00* बजे कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को धमकाया और अपमानजनक शब्द कहे।

श्री सोगरा ने भी अपना जवाब प्रस्तुत करने के लिए *07.12.99* के बाद दस दिन का समय मांगा था। फिर से अपने लिखित जवाब

(27.11.99) में और दिए गए कारण तार्किक नहीं हैं। श्री सोगरा का एकमात्र उद्देश्य कार्यवाही को समाप्त न होने देना है। सक्षम अधिकारी ने सुनवाई पूरी होने के बाद भी दोषी कर्मचारी को अपने गवाहों को पेश करने का एक और अवसर प्रदान किया। फिर भी दोषी कर्मचारी ने अपना बचाव/गवाह प्रस्तुत नहीं किया। पूरी कार्यवाही के दौरान, विभिन्न अतार्किक मांगें की गईं, जिससे कार्यवाही में बाधा उत्पन्न हुई और कार्यवाही को लंबे समय तक समाप्त होने से रोका गया।

इस प्रकार श्री पदमचंद सोगरा भारतीय जीवन बीमा निगम *(*कर्मचारी*)* विनियम, *1960* के विनियम *21* और *24* के उल्लंघन का दोषी है और विनियम *39* के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी है।

इस रिपोर्ट के साथ निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न हैं*:-*

1. दिनांक *12.03.1999* के आरोप पत्र की प्रति।
2. प्रदर्शसंख्या पी-*1* से पी-*27* की प्रतियां।
3. प्रदर्शसंख्या डी-*1* से डी-*3* की प्रतियां।
4. श्री एस.एस. वर्मा को जाँच अधिकारी और श्री भगवान चेल्लारामानी को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के दिनांक *02.06.99* के आदेश की प्रति।
5. उपरोक्त उल्लिखित गवाहों द्वारा दी गई गवाही की प्रतियां।
6. उपरोक्त उल्लिखित सभी जाँच कार्यवाहियों की प्रतियां।

हस्ताक्षरित/-
स्थान*:-* उदयपुर *(*एस.एस. वर्मा*)*
दिनांक*:-14.12.99* जाँच अधिकारी

8. इन रिपोर्टों के अवलोकन से पता चलता है कि जाँच अधिकारी ने सभी उपलब्ध सामग्री और साक्ष्य पर उचित विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष दर्ज किए।

9. इन जाँच रिपोर्टों की अनुशासनात्मक प्राधिकारी द्वारा समीक्षा की गई, जिसने उनके अवलोकन पर, मेरे विचार से, दंड आदेशों को उचित रूप से पारित किया, क्योंकि वे स्व-व्याख्यात्मक हैं और जाँच निष्कर्षों पर आधारित हैं।

10. वास्तव में, चुनौती दिए गए दंड के मुकाबले जाँच रिपोर्टों की जाँच से पता चलता है कि दंड लगाना दुराचार की गंभीरता के अनुपात में है/था। इस तरह के दुराचार—जुआ खेलने में शामिल होना, सहकर्मियों के साथ दुर्व्यवहार करना, और दूसरे कर्मचारी पर शारीरिक हमला करना—कार्यस्थल अनुशासन बनाए रखने और संस्थागत अखंडता को बनाए रखने के लिए सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की मांग करता है। याचिकाकर्ता ने अपीलीय प्राधिकारी से अपील की, जिसने विस्तृत तर्क के साथ दंड की

पुष्टि की। अपीलीय प्राधिकारी ने, दंड की पुष्टि करते हुए, तर्क प्रदान किया और याचिकाकर्ता की चुनौती में कोई योग्यता नहीं पाई।

11. यह तर्क कि कथित जुआ खेलने की घटना कार्यालय समय के बाहर हुई थी, असमर्थनीय है। किसी भी संगठन के कर्मचारियों से, विशेष रूप से सार्वजनिक विश्वास और वित्तीय सुरक्षा से निपटने वाले, हर समय नैतिक आचरण बनाए रखने की उम्मीद की जाती है। इसके अलावा, सहकर्मियों पर शारीरिक हमला और धमकी, जैसा कि कई गवाहों की गवाही से सिद्ध होता है, अनुशासनहीनता और कार्यस्थल शत्रुता का एक पैटर्न प्रदर्शित करता है जिसे माफ नहीं किया जा सकता है।

12. प्रक्रियात्मक अनियमितताओं के याचिकाकर्ता के दावे सारहीन हैं। उसे अपना बचाव करने का हर अवसर प्रदान किया गया था, लेकिन इसके बजाय उसने तुच्छ मांगों के माध्यम से कार्यवाही में देरी करने की मांग की, जैसे कि बार-बार बचाव सहायक को बदलने का अनुरोध करना और अप्रासंगिक दस्तावेजों के प्रावधान पर जोर देना।

13. जाँच अधिकारी ने गवाहों की गवाही को सावधानीपूर्वक दर्ज किया, और निष्कर्ष केवल अनुमान के बजाय ठोस साक्ष्य पर आधारित थे। इसी तरह, अपीलीय प्राधिकारी का दंड को बरकरार रखने का निर्णय न तो मनमाना था और न ही अनुचित। यह भविष्य में इस तरह के दुराचार को रोकने के लिए अनुशासनात्मक उपायों को लागू करने की आवश्यकता की एक मापी गई और सुविचारित पुष्टि थी। ऐसे मामलों में नरम दृष्टिकोण अनुशासनात्मक ढांचे को कमजोर करेगा और एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा, जिससे संस्थागत अधिकार का क्षरण होगा।

14. याचिकाकर्ता के विरुद्ध जबरदस्त साक्ष्य और हर चरण पर उचित प्रक्रिया का पालन किए जाने के आलोक में, न्यायिक अनुग्रह के लिए कोई आधार मौजूद नहीं है।

15. परिणामस्वरूप, मुझे हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं मिलता है।

16. तदनुसार, याचिकाएँ खारिज की जाती हैं। सभी लंबित आवेदन, यदि कोई हों, भी निपटारा किए जाते हैं।

(अरुण मोंगा), न्यायमूर्ति

145-146-एस.पी./एस.के.एम./-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है: हाँ / नहीं

अस्वीकरण:- स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय केवल वादियों के अपनी भाषा में लाभ के लिए हैं तथा इनका किसी अन्य उद्देश्य के लिए उपयोग नहीं किया जा सकता। निर्णय का अंग्रेजी संस्करण सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रामाणिक होगा और इसे लागू करने में प्राथमिकता दी जाएगी।

एडवोकेट विष्णु जांगिड़